

the new industrial and trade policies so as to make them contribute significantly to the foreign exchange earnings of the country.

The table below gives the inflow and outflow of foreign exchange for the years 1986-87, 1987-88, 1988-89 1989-90 for 50 industrial houses.

(Value Rs Crores)

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
Foreign Exchange inflow	539	1176	1993	2715
Foreign Exchange Outflow	1058	4251	3024	387

The Statement at Annexure gives the details of the export performance of the 50 select industrial houses for the year 1986-87 to 1989-90.

[See Appendix CLX, Annexure No. 48]

“तुलसी सदन पुस्तकालय” का कार्यक्रम

1175. श्रीमती शोभा वर्मा :

श्रीमती कैलाशपति :

श्री कपिल वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भाषाओं का एकमात्र पुस्तकालय “तुलसी सदन” गत दो वर्षों से बंद पड़ा है ; यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) यह पुस्तकालय कब स्थापित किया गया था ;

(ग) इस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं और प्रत्येक वर्ष खरीदी गयी पुस्तकों का पूर्ण व्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार इस पुस्तकालय का विलय दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के साथ करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हाँ, व्यापक मरम्मत के लिए ।

(ख) 1974 में

(ग) लगभग 1,44,500 जिन्हें अनुपम में दर्शाया गया है । [लेखिए परिशिष्ट CLX परिपत्र सं० 49]

(घ) जी, हाँ ।

(ङ) जिससे कि पुस्तकों का प्रयोग अधिक से अधिक हो सके ।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मजदूरी

1176. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अगस्त, 1991 के “नवभारत टाइम्स” में “आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने गिरफ्तारी दी” शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार का और दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि आंगनवाड़ी योजना के अन्तर्गत कार्यरत महिलाओं को अब तक सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि इस योजना के अन्तर्गत उच्च पर कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया गया है और उन्हें समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की दी जा रही सुविधाओं के समान सभी सुविधाएँ दी गई हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस योजना के अधीन क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही महिलाओं को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

युवा कार्य तथा खेल और महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कु० ममता बेनर्जी) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना (आई सी डी एस) राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के जरिए कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा दो श्रेणियों के कार्यकर्ता रखे जाते हैं—स्टाफ जिसमें कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अपर/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर (मुख्य-सेविहए) तथा राज्य स्तर पर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और परियोजना स्तर पर अनुसूचिवीय स्टाफ आता है। दूसरी श्रेणी में निचले स्तर के कार्यकर्ता अर्थात् आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आती हैं। वे अंशकालिक, अवैतनिक, स्वयंसेवी कार्यकर्ता होते हैं और सामान्यतः उसी गांव से लिए जाते हैं जहाँ आंगनवाड़ी केन्द्र स्थित होता है। दोनों श्रेणियों के स्टाफ को भर्ती संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा की जाती है।

(घ) समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) योजना सामुदायिक सहभागिता के सिद्धान्त पर आधारित है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं स्थानीय समुदाय से ली गई अंशकालिक, स्वयंसेवी और अवैतनिक कार्यकर्ता होते हैं और उन्हें सरकारी कर्मचारी माने जाने से सामुदायिक सहभागिता का सिद्धान्त ही समाप्त हो जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ियों में चार घंटे काम करती हैं और उन्हें प्रति दिन आधा घंटा घरों का दौरा करना होता है। सहायिकाओं के लिए गृह-दौरे करना अपेक्षित नहीं है।

Overinvoicing in import of drugs

1177. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that duty free import of bulk drugs and formulations is giving rise to overinvoicing;

(b) if so, what is the number of such instances that have come to the notice of his Ministry;

(c) what is the rationale behind duty free import of the products which are not price controlled;

(d) what are the names of finished medicines and bulk drugs which are exempted from price control and where his Ministry has either allowed exemption from or concession of customs duty during the last three years;

(e) whether it is a fact that his Ministry did not agree to certain proposals in the drug sector for hike in duties of bulk drugs and intermediates which are produced from basic stage and finished medicines being produced indigenously;

(f) if so, what are the names of such items and the reasons for rejecting the proposal; and

(g) what is the total loss in foreign exchange due to this lapse?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) Information regarding the number of instances of overinvoicing of imports of duty free bulk drugs and formulations is not readily available. The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Exemption from import duty is extended to bulk drugs and intermediates so as to encourage indigenous production from the more basic